



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 1, 2012/श्रावण 10, 1934

No. 170]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 1, 2012/SHRAVANA 10, 1934

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2012

फा. सं. 1-सीए (7)/145/2012.—चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 में और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप विनियमों को, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4, तारीख 23 फरवरी, 2012 में भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान की अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/145/2012 तारीख 23 फरवरी, 2012 के अधीन, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से पैंतालिस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व ऐसे व्यक्तियों से, जिनकी उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 28 फरवरी, 2012 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में, जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर संस्थान की परिषद् द्वारा विचार किया गया था ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद्, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) विनियम, 2012 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 2 के उपविनियम (1) में,-

(i) खंड (xiii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(xiii) क) ‘नियमों’ से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं ;”;

(ii) खंड (xv) में “या किसी उप” शब्दों के स्थान पर “या किसी अपर या संयुक्त या उप” शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त विनियमों के विनियम 25ग में “सामान्य प्रवीणता परीक्षा” शब्दों के, जहां कहीं वे आते हैं, स्थान पर क्रमशः “सामान्य प्रवीणता पाठ्यक्रम” शब्द रखे जाएंगे ।

4. उक्त विनियमों के विनियम 25घ में,-

(i) उपविनियम (1) में,-

(क) “केन्द्रीय सरकार” शब्दों के पश्चात् “या राज्य सरकार” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) “उनके समतुल्य” शब्दों के पश्चात् “स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(ii) उपविनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(1क) विनियम 2 के उपखंड (ix) में निर्दिष्ट किसी स्नातक या स्नातकोत्तर को इस विनियम के अधीन सामान्य प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की जाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति -

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय (जिसके अंतर्गत कोई मुक्त विश्वविद्यालय भी है) में लेखा, संपरीक्षा, वाणिज्य विधि, निगम विधि, अर्थशास्त्र, प्रबंध (जिसके अंतर्गत वित्तीय प्रबंध भी है), कराधान (जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष कर विधि और अप्रत्यक्ष कर विधि भी है), लागत, कारबार प्रशासन या प्रबंध लेखा में से तीन विषयों का अध्ययन करके, उस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित उन विषयों में 100 अंक प्रत्येक की परीक्षा में से कुल अंकों के न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों या समतुल्य ग्रेड को प्राप्त करते हुए वाणिज्य में स्नातक या स्नातकोत्तर है ; या

(ii) खंड (i) में निर्दिष्ट से भिन्न स्नातक या स्नातकोत्तर है जिसने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय (जिसके अंतर्गत मुक्त विश्वविद्यालय भी है) द्वारा संचालित परीक्षा में कुल अंकों में से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य ग्रेड प्राप्त किए हैं ।

(1ख) लागत और संकर्म लेखा अधिनियम, 1959 (1959 का 23) के अधीन गठित भारतीय लागत और संकर्म लेखा संस्थान या कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) के अधीन गठित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को भी इस विनियम के अधीन सामान्य प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की जाएगी ।

स्पष्टीकरण.- उपविनियम (1क) और (1ख) के प्रयोजनों के लिए,-

(i) अंकों के प्रतिशत की संगणना के लिए, ऐसे विषयों में, जिनमें विश्वविद्यालय (जिसके अंतर्गत मुक्त विश्वविद्यालय भी है) व्यक्ति से केवल उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने की अपेक्षा करता है और जिनमें उच्च अंकों के लिए कोई विशेष प्रत्यय नहीं दिया जाता है, अर्जित अंकों को नजरअंदाज किया जाएगा ; और

(ii) आधे या अधिक के किसी भिन्न को अगले पूर्ण अंक के रूप में माना जाएगा ।” ।

5. उक्त विनियमों के विनियम 28ग में,-

(क) “वृत्तिक सक्षमता परीक्षा” शब्दों के, जहां कहीं वे आते हैं, स्थान पर क्रमशः “इंटरमीडिएट (वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपविनियम (1) में,-

(i) खंड (क) में,-

(क) “केन्द्रीय सरकार” शब्दों के पश्चात् “या राज्य सरकार” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) “उनके समतुल्य” शब्दों के पश्चात् “स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) (क) खंड (ख) में, “कार्य” शब्द के स्थान पर “सेवा” शब्द रखा जाएगा ;

(ख) “परीक्षा का आयोजन किया जाता है” शब्दों के पश्चात् “और वह उक्त मास की पहली तारीख को ऐसा करना जारी रखता है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) दूसरे परंतुक में, “वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा II) में बैठने के लिए” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् “ और वह खंड (ख) के अधीन अधिकथित शर्त को पूरा करता है” शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

6. उक्त विनियमों के विनियम 28घ में,-

(क) “एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम” शब्दों के, जहां कहीं वे आते हैं, स्थान पर क्रमशः “इंटरमीडिएट (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) पाठ्यक्रम” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) कोई भी अभ्यर्थी तब तक इंटरमीडिएट (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) पाठ्यक्रम के किसी भी स्तर हेतु नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने -

(क) भारत में विधि द्वारा गठित किसी परीक्षा निकाय द्वारा इन विनियमों के अधीन संचालित या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी परीक्षा में सामान्य प्रवीणता परीक्षा और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10 + 2 परीक्षा) उत्तीर्ण न कर ली हो, जो कि किसी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजन के लिए उसकी समतुल्य है ; या

(ख) विनियम 25घ के अधीन सामान्य प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट न प्राप्त कर ली हो ।”;

(ग) उपविनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(2क) उपविनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जो किसी स्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहा है, इंटरमीडिएट (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) पाठ्यक्रम के लिए अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, जिसे उसके द्वारा, स्नातक परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठने की तारीख से छह मास से अधिक ऐसी अवधि के भीतर, जिसे परिषद् द्वारा अभिनिश्चित किया जाए, स्नातक परीक्षा में विनियम 25घ के उपविनियम (1क) में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अंकों के साथ उत्तीर्ण करने का समाधानप्रद सबूत प्रस्तुत किए जाने पर अभिपुष्ट किया जाएगा :

परंतु यदि ऐसा अभ्यर्थी पूर्वोक्त अवधि के भीतर ऐसा सबूत प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो, उसके अनंतिम रजिस्ट्रीकरण को रद्द किया जाएगा और उसके द्वारा संदत्त यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण फीस या ट्यूशन फीस का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा और इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए उसे उसके द्वारा प्राप्त की गई किसी सैद्धांतिक शिक्षा के लिए कोई प्रत्यय नहीं दिया जाएगा ।” ।

7. उक्त विनियमों के विनियम 28ड में,-

(क) “एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा”, “एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम” और “वृत्तिक सक्षमता परीक्षा” शब्दों के, जहां कहीं वे आते हैं, स्थान पर क्रमशः “इंटरमीडिएट (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा”, “इंटरमीडिएट (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) पाठ्यक्रम” और “इंटरमीडिएट (वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपविनियम (1) में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ परंतु ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसे विनियम 25घ के उपविनियम (1क) के अधीन सामान्य प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की गई है और जिसे इंटरमीडिएट (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) पाठ्यक्रम के लिए नामांकित किया गया है, विनियम 50 के अधीन व्यवहारिक प्रशिक्षण के 9 मास पूरा होने के पश्चात् परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा ।”;

8. उक्त विनियमों के विनियम 29ख में, “वृत्तिक सक्षमता परीक्षा”, शब्दों के, जहां कहीं वे आते हैं, पश्चात् क्रमशः “या इंटरमीडिएट (वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा” शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

9. उक्त विनियमों के विनियम 29ग में,-

(अ) उपविनियम (1) में,-

(i) खंड (i) में, -

(क) “वृत्तिक सक्षमता परीक्षा” शब्दों के स्थान पर “इंटरमीडिएट (वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) अंत में आने वाले “और” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ii) में, “परीक्षा का आयोजन किया जाता है” शब्दों के पश्चात् “या उस मास के, जिसमें परीक्षा का आयोजन किया जाता है, प्रथम दिन विनियम 50 के अधीन व्यवहारिक प्रशिक्षण के अंतिम छह मास को पूरा कर रहा है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(iii) वह परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित रीति में, इस प्रभाव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि उसने उस मास की पहली तारीख को जिसमें परीक्षा का आयोजन किया जाता है, ऐसी अवधि के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है ; और

(iv) उसने इन विनियमों के अधीन ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाए, सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संबंधी अग्रणी पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है ।”;

(iv) परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जिसने परिषद् द्वारा विनियम 28ख के उपविनियम (5) के अधीन यथाविनिश्चित पाठ्यचर्या के अधीन वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा II) को उत्तीर्ण कर लिया है और जिसने उस मास से, जिसमें परीक्षा का आयोजन किया जाता है, पूर्ववर्ती मास की अंतिम तारीख को या उससे पूर्व सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए अपेक्षित व्यवहारिक प्रशिक्षण को पूरा कर लिया है या वह उस मास की पहली तारीख को जिसमें परीक्षा का आयोजन किया जाता है, व्यवहारिक प्रशिक्षण के अंतिम बारह मासों को पूरा कर रहा है जिसके अंतर्गत कोई आधिक्य छुट्टी भी है और उसने उक्त अध्ययन पाठ्यक्रम को और साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संबंधी अग्रणी पाठ्यक्रम को भी पूरा कर लिया है, अंतिम परीक्षा में बैठने दिया जाएगा ।

(आ) उपविनियम (2) में,-

(क) “एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा” शब्दों के पश्चात् “या इंटरमीडिएट (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा” शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) अंत में आने वाले “परीक्षा का आयोजन किया जाता है” शब्दों के पश्चात् “उसने पूर्वोक्त अध्ययन पाठ्यक्रम को और साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संबंधी अग्रणी पाठ्यक्रम को भी पूरा कर लिया है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

10. उक्त विनियमों के विनियम 31 में,-

(i) खंड (ii) में, “वृत्तिक सक्षमता परीक्षा” शब्दों के स्थान पर “इंटरमीडिएट (वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (iii) में, “एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम” शब्दों के स्थान पर “इंटरमीडिएट (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) पाठ्यक्रम” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

11. उक्त विनियमों के विनियम 36क के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“36क. सामान्य प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षा - किसी अभ्यर्थी के संबंध में सामान्यतः यह घोषणा कि उसने सामान्य प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, तब की जाएगी यदि वह प्रत्येक वर्ग में एक ही बार में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और सभी वर्गों में कुल न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, यह ऐसी रीति में, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए, ऋणात्मक अंक प्रणाली के सिद्धांत के अधीन रहते हुए किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण.- शंका के निवारण के लिए यह घोषणा की जाती है कि इस विनियम के उपबंध चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) विनियम, 2012 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् होने वाली सामान्य प्रवीणता परीक्षा को लागू होंगे ।” ।

12. उक्त विनियमों के विनियम 37ख में, “वृत्तिक सक्षमता परीक्षा” शब्दों के, जहां कहीं वे आते हैं, स्थान पर क्रमशः “इंटरमीडिएट (वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

13. उक्त विनियमों के विनियम 37ग में,-

(i) “एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा” शब्दों के, जहां कहीं वे आते हैं, स्थान पर क्रमशः “इंटरमीडिएट (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) “वृत्तिक सक्षमता परीक्षा” शब्दों के, जहां कहीं वे आते हैं, स्थान पर क्रमशः “इंटरमीडिएट (वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(iii) उपविनियम (2) के खंड (क) का लोप किया जाएगा ।

14. उक्त विनियमों के विनियम 40 में,-

(i) “वृत्तिक सक्षमता परीक्षा” शब्दों के स्थान पर “इंटरमीडिएट (वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) “एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा” शब्दों के स्थान पर “इंटरमीडिएट (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

15. उक्त विनियमों के विनियम 43 में,-

(i) उपविनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(2क) चार्टर्ड एकाउंटेंटों की किसी फर्म के पूर्णकालिक नियोजन में लगा कोई सदस्य एक आर्टिकलड सहायक को प्रशिक्षण देने का हकदार होगा, परंतु यह कि वह उसी फर्म में लगातार तीन वर्ष की अवधि से नियोजन में रहा हो ।”;

(ii) उपविनियम (3) में खंड (i) का लोप किया जाएगा ।

16. उक्त विनियमों के विनियम 45 में,-

(i) “एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम” शब्दों के, जहां कहीं वे आते हैं, स्थान पर क्रमशः “इंटरमीडिएट (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) पाठ्यक्रम” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) उपविनियम (1) के खंड (ख) में,-

(क) उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(i) उसने इन विनियमों के अधीन आयोजित वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा II) या इंटरमीडिएट परीक्षा के समूह I स्तर या लेखा तकनीशियन स्तर को उत्तीर्ण कर लिया हो या उसे विनियम 25घ के उपविनियम (1क) के अधीन सामान्य प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की गई हो ; और”;

(ख) खंड (ii) में, “इस प्रकार विनिर्दिष्ट” शब्दों के पश्चात् “और” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ग) उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

2855 GI/12-2

“(iii) उसने ऐसी अवधि के लिए ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाए, अनुकूलन पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है।”;

(iii) उपविनियम (2) में,-

(क) “केन्द्रीय सरकार” शब्दों के पश्चात् “या राज्य सरकार” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) “उनके समतुल्य” शब्दों के पश्चात् “स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

17. उक्त विनियमों के विनियम 50 में,-

(i) तीसरे परंतुक में, “वृत्तिक सक्षमता परीक्षा” शब्दों के स्थान पर “इंटरमीडिएट (वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) चौथे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि इंटरमीडिएट (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) पाठ्यक्रम के लिए नामांकित कोई अभ्यर्थी, इंटरमीडिएट (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा के समूह I स्तर या लेखा तकनीशियन स्तर को उत्तीर्ण करने पर तीन वर्ष के आर्टिकल प्रशिक्षण के लिए पात्र होगा :

परंतु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो स्नातक या स्नातकोत्तर है और जिसे सामान्य प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी गई है, इंटरमीडिएट (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण होने पर तीन वर्ष के आर्टिकल प्रशिक्षण के लिए पात्र होगा ।” ।

18. उक्त विनियमों के विनियम 51 के उपविनियम (1) में, “वृत्तिक सक्षमता परीक्षा” शब्दों के स्थान पर “इंटरमीडिएट (वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

19. उक्त विनियमों के विनियम 51ख के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“51ग. सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संबंधी अग्रणी पाठ्यक्रम - कोई अभ्यर्थी सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संबंधी अग्रणी पाठ्यक्रम पूरा करेगा, जैसा कि परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए, जो एक सौ घंटों से कम नहीं होगा और पांच सौ घंटों से अधिक नहीं होगा और यह पाठ्यक्रम ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर पूरा किया जाएगा, जो कि परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए ।” ।

20. उक्त विनियमों के विनियम 69 में,-

(क) उपविनियम (1) के खंड (ख) में उपखंड (ii) और (iii) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(ii) उसने इन विनियमों के अधीन आयोजित वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा II) या इंटरमीडिएट (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा के समूह I स्तर या लेखा तकनीशियन स्तर को उत्तीर्ण कर लिया हो या उसे विनियम 25घ के उपविनियम (1क) के अधीन सामान्य प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की गई हो ; और

(iii) उसने परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिश्चित रीति में और समय के भीतर ऐसी अवधि के कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम या सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है ; और”

(ख) उप खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(iv) उसने ऐसी अवधि के लिए ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाए, अनुकूलन पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है ।” ।

21. उक्त विनियमों के विनियम 72 के उपविनियम (1) में, “वृत्तिक सक्षमता परीक्षा” शब्दों के स्थान पर “इंटरमीडिएट (वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

22. उक्त विनियमों के विनियम 72ख के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“72ग. सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संबंधी अग्रणी पाठ्यक्रम - कोई अभ्यर्थी सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संबंधी अग्रणी पाठ्यक्रम पूरा करेगा, जैसा कि परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए, जो एक सौ घंटों से कम नहीं होगा और पांच सौ घंटों से अधिक नहीं होगा और यह पाठ्यक्रम ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर पूरा किया जाएगा, जो कि परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए।”

23. उक्त विनियमों के विनियम 127 के उपविनियम (1) में, मद 4 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

“4. बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य।”

24. उक्त विनियमों के विनियम 130 के उपविनियम (2) में,-

(i) खंड (xvii) के अंत में आने वाले “और” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (xvii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(xvii) क) उपयोगी जानकारी के प्रसार के लिए न्यूज लेटर का प्रकाशन ;

(xvii) ख) वृत्तिक संगतता के विषयों पर सतत वृत्तिक शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन ; और”।

25. उक्त विनियमों के विनियम 134 में,-

(i) उपविनियम (1) में,-

(क) “वर्ष के अप्रैल” शब्दों के स्थान पर “वित्तीय वर्ष के अप्रैल” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि यदि सुसंगत तारीख को रजिस्टर में वृत्तिक पता उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो रजिस्टर में दर्ज आवास का पता उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को अवधारित करेगा ;

परंतु यह भी कि, उस दशा में, जहां किसी सदस्य का वृत्तिक पता भारत से बाहर है और वह मतदान करने के लिए पात्र है तो उसके क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र का अवधारण, उसके विदेश जाने से तुरंत पूर्व भारत में रजिस्ट्रीकृत उसके वृत्तिक पते या सुसंगत तारीख को रजिस्टर में दर्ज भारत में उसके आवास के पते, जो भी पश्चातवर्ती हो, के अनुसार किया जाएगा।”;

(ii) उपविनियम (2) में,-

(क) “वर्ष के अप्रैल” शब्दों के स्थान पर “वित्तीय वर्ष के अप्रैल” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “निर्वाचन की तारीख को” शब्दों के स्थान पर “नामांकनों की संवीक्षा की अंतिम तारीख को” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“परंतु कोई व्यक्ति क्षेत्रीय परिषद् के निर्वाचन के लिए खड़ा होने का पात्र नहीं होगा, यदि -

(क) वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा है ;

(ख) वह तीन लगातार कार्यावधियों से अधिक के लिए क्षेत्रीय परिषद् का सदस्य है या निर्वाचित किया गया है ; या

(ग) वह विनियम 137 के अधीन अध्यक्ष है या अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है :

परंतु यह और कि, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे वृत्तिक या अन्य कदाचार का दोषी पाया गया है और जिसके नाम को रजिस्टर से हटा दिया गया है या जिस पर जुर्माने की शास्ति अधिरोपित की गई है, निम्नलिखित दशाओं में, यथास्थिति, रजिस्टर से नाम हटाए जाने की अवधि पूरा होने या जुर्माने के संदाय की तारीख से, क्षेत्रीय परिषद् का निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा,-

(i) अधिनियम की पहली अनुसूची के अंतर्गत आने वाले कदाचार की दशा में तीन वर्ष की अवधि के लिए ;

(ii) अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले कदाचार की दशा में छह मास की अवधि के लिए ;

परंतु यह भी कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो क्षेत्रीय परिषद् का संपरीक्षक रहा है, उस क्षेत्रीय परिषद् का संपरीक्षक न रहने पर तीन वर्ष की अवधि के लिए उस क्षेत्रीय परिषद् के निर्वाचन में खड़ा होने का पात्र नहीं होगा ।”;

(iii) उपविनियम (3) में “विनियम 85 के अधीन” शब्दों और अंकों के स्थान पर “चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 की अनुसूची 3 के साथ पठित नियम 8 के अधीन” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(iv) उपविनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ (4) (i) परिषद् निर्वाचन की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, मतदान हेतु पात्र सदस्यों की एक सूची का प्रकाशन करेगी, जिसमें निम्नलिखित को स्पष्ट और पृथक् रूप से दर्शित किया जाएगा,-

(क) क्या मतदाता कोई एसोसिएट है अथवा कोई फेलो है ;

(ख) मतदान के लिए सदस्य की पात्रता का विनिश्चय करने के लिए उपविनियम (1) के अधीन यथावधारित प्रत्येक सदस्य का पता ;

(ग) भारत से बाहर निवास करने वाले किसी मतदाता की दशा में, खंड (ख) के अधीन भारत में उसके पते के अलावा, भारत से बाहर का उसका पता यदि संबद्ध मतदाता द्वारा उसे संस्थान को प्रस्तुत किया गया है ;

(घ) मतदाता द्वारा संस्थान को प्रस्तुत किए गए इंटरनेट पते या ई-मेल पते ब्यौरे, परंतु मतदाता द्वारा मतदाताओं की सूची में उसे सम्मिलित करने के लिए अभिव्यक्त रूप से सहमति प्रदान की गई हो ;

(ङ) वह रीति, जिसमें मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा ; और

(च) उस दशा में, जहां मतदाता निर्वाचन केन्द्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा, ऐसे मतदान केन्द्र का संख्यांक और पता जिसमें मताधिकार का प्रयोग किया जाना है ।

(ii) इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी सदस्य का, उस रीति का अवधारण करने के लिए, जिसमें वह मत डालने के लिए हकदार होगा मतदाताओं की सूची में प्रकाशित पता,

निर्वाचन क्षेत्र और वह मतदान केन्द्र, जिससे वह मतदान करने के प्रयोजन के लिए संबंध रखता है, अंतिम होंगे।

- (iii) किसी सदस्य का नाम मतदान करने के लिए पात्र सदस्यों की सूची में शामिल किए जाने पर, उसे निर्वाचन में मतदान करने का कोई आत्यंतिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जो कि इन नियमों तथा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन होगा।
- (iv) मतदान करने के लिए पात्र सदस्यों की सूची क्षेत्रीय परिषद् के मुख्यालय और उसकी शाखाओं में परिषद् द्वारा नियत की जाने वाली कीमत के संदाय पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- (v) सूची की उपलब्धता के बारे में एक उद्घोषणा क्षेत्रीय परिषद् की वेबसाइट, क्षेत्रीय परिषद् की सूचना पट्ट और साथ ही क्षेत्रीय परिषद् की शाखाओं के सूचनापट्ट पर, जहां कहीं वे विद्यमान हों, रखी जाएगी।
- (vi) यदि मतदान करने के लिए पात्र सदस्यों की सूची में कोई लिपिकीय त्रुटि या लोप पाया जाता है तो सचिव एक उपयुक्त शुद्धि पत्र जारी करके किसी भी समय ऐसी त्रुटि को ठीक कर सकेगा।¹;

(v) उपविनियम (6) में,-

(i) खंड (i) में, “उपयुक्त प्ररूप” शब्दों के स्थान पर “परिषद् द्वारा अनुमोदित प्ररूप” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ii) परिषद् द्वारा अनुमोदित प्ररूप में इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट अपेक्षित फीस, प्रतिभूति निक्षेप और अन्य पत्रों के साथ सचिव को, उसके नाम पर अधिसूचित तारीख को सांय छह बजे से पूर्व परिदत्त :

परंतु अंतिम तारीख और निर्वाचन के लिए अधिसूचित समय के पश्चात् प्राप्त हुए किसी नामांकन पर, पैनल द्वारा नामांकनों की संवीक्षा हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) नामांकन की प्राप्ति पर सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उसकी अभिस्वीकृति जारी की जाएगी, जिसमें नामांकन प्ररूप की प्राप्ति के समय और तारीख का उल्लेख किया जाएगा।¹;

(vi) उपविनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम और स्पष्टीकरण अंतःस्थपित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(6क) नामांकन केवल तभी विधिमान्य होगा यदि उसके साथ अभ्यर्थी द्वारा मांगी गई जानकारी को अंतर्विष्ट करने वाला एक कथन लगा होगा और वह अभ्यर्थी द्वारा सत्यापित होगा।

स्पष्टीकरण.- इस उपविनियम के प्रयोजन के लिए, एक विधिमान्य नामांकन से ऐसा कोई नामांकन अभिप्रेत है जिसमें नामांकन प्ररूप के माध्यम से मांगी गई सभी विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं और एक या अधिक विशिष्टियों को सम्मिलित न करने वाला अपूर्ण नामांकन नामंजूर किए जाने के लिए दायी होगा।¹;

(vii) उपविनियम (7) में, “एक हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर “पच्चीस हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(viii) उपविनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंतःस्थपित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(7क) निर्वाचन में खड़े होने वाला कोई अभ्यर्थी इस अध्याय में यथाउपबंधित फीस के अलावा, फाइल किए गए नामांकनों की संख्या पर ध्यान न देते हुए प्रतिभूति निक्षेप के रूप में दस हजार रुपए की एक राशि का संदाय करेगा, जिसे संबद्ध क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन में पड़े मूल मतों में से उसके द्वारा एक प्रतिशत से अन्यून मत प्राप्त होने की दशा में जब्त कर लिया जाएगा।¹;

2855 GI/12-3

(ix) उपविनियम (8) में, “परामर्श से अनुमोदन के साथ” शब्दों के स्थान पर “पूर्व अनुमोदन के साथ” शब्द रखे जाएंगे ;

(x) उपविनियम (9) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ (9क) अध्यक्ष अपना निर्णय देते हुए,-

(क) उपविनियम (9) के अधीन उसे विनिर्दिष्ट विवाद को खारिज कर सकेगा ;

(ख) समी या किसी निर्वाचित अम्भ्यर्थी के निर्वाचन को शून्य घोषित कर सकेगा ;

(ग) समी या किसी निर्वाचित अम्भ्यर्थी के निर्वाचन को शून्य घोषित कर सकेगा और आवेदक या किसी अन्य अम्भ्यर्थी को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित कर सकेगा ; या

(घ) लागत के संबंध में ऐसा कोई आदेश पारित कर सकेगा जिसे वह उपयुक्त समझे ।”

(xi) उपविनियम (10) में, “इन विनियमों के अध्याय 6 में विहित” शब्दों और अंकों के स्थान पर “चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 में विनिर्दिष्ट” शब्द, कोषक और अंक रखे जाएंगे।

26. उक्त विनियमों के विनियम 135 के उपविनियम (4) के स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ।

27. उक्त विनियमों के विनियम 137 में,-

(i) उपविनियम (1) के खंड (i) में, “सितम्बर” शब्द के स्थान पर “फरवरी” शब्द रखा जाएगा ;

(ii) उपविनियम (7) के खंड (i) में, मद (ड) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“ (च) सतत् वृत्तिक शिक्षा समिति ।”

(iii) उपविनियम (11) में, “सितम्बर” शब्द के स्थान पर “फरवरी” शब्द रखा जाएगा ।

28. उक्त विनियमों के विनियम 141 के उपविनियम (1) के परंतुक में “सितम्बर” शब्द के स्थान पर “फरवरी” शब्द रखा जाएगा ।

29. उक्त विनियमों के विनियम 149 के उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(1) क्षेत्रीय परिषद्, क्षेत्र के कुल सदस्यों के न्यूनतम 10 प्रतिशत सदस्यों या क्षेत्र के कम से कम सात सौ पचास सदस्यों, इनमें जो भी कम हो, द्वारा लिखित में अध्यक्षता किए जाने पर एक विशेष साधारण बैठक का आयोजन कर सकेगी ।”

30. उक्त विनियमों के विनियम 159 में,-

(i) उपविनियम (1) में “100 सदस्य” अंकों और शब्द के स्थान पर “150 सदस्य” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपविनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(1क) परिषद्, भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी जिले में ऐसे स्थान पर, जहां क्षेत्रीय परिषद् का न तो मुख्यालय और न ही उसकी कोई शाखा अवस्थित है, क्षेत्रीय परिषद् की शाखा की स्थापना कर सकेगी, परंतु यह कि उस जिले में न्यूनतम 100 सदस्यों का पता रजिस्ट्रीकृत हो ।”

31. उक्त विनियमों के विनियम 161 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ 161क. टेलीकांफ्रेंसिंग या वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से परिषद् की बैठकें - परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाने वाली शर्तों के अधीन रहते हुए किसी भी समय टेलीकांफ्रेंसिंग या वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से परिषद् की बैठक बुलाई जा सकेगी ।”

32. उक्त विनियमों के विनियम 169 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ 169क. टेलीकांफ्रेंसिंग या वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से स्थायी समिति की बैठकें - ऐसी समिति द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाने वाली शर्तों के अधीन रहते हुए किसी भी समय टेलीकांफ्रेंसिंग या वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से स्थायी समिति की बैठक बुलाई जा सकेगी ।”

33. उक्त विनियमों के विनियम 177 के उपविनियम (3) में “विनियम 169” शब्द और अंकों के पश्चात् “,169क” अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

34. उक्त विनियमों के विनियम 184 में, उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(1) जहां परिषद् द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणपत्र का धारक उस प्रमाणपत्र को खो देता है, वहां परिषद् आवेदक द्वारा इस प्रभाव के कि ऐसा प्रमाणपत्र उसके कब्जे में था और वह खो गया था, शपथपत्र द्वारा सम्यक् रूप से समर्थित इस निमित्त आवेदन किए जाने पर-

(क) ऐसोसिएट या फेलो के रूप में सदस्यता प्रमाणपत्र या वृत्ति प्रमाणपत्र की दशा में 500 रुपये की फीस के संदाय पर द्वितीय प्रमाणपत्र जारी कर सकेगी ; और

(ख) इन विनियमों के अधीन जारी अन्य प्रमाणपत्रों की दशा में 200 रुपये की फीस के संदाय पर ऐसा द्वितीय प्रमाणपत्र जारी कर सकेगी ।”

35. उक्त विनियमों के विनियम 192 के परंतुक में,-

(i) खंड (ख) में, अंत में आने वाले “और” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(घ) परिषद् द्वारा समय-समय पर संकल्प द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली कतिपय प्रबंध परामर्शी सेवाओं की दशा में, फीस ऐसे प्रतिशत आधार पर आधारित हो सकेगी, जो ऐसे कार्य के निष्कर्षों या परिणामों पर निर्भर हो ;

(ङ) कतिपय निधि जुटाने वाली सेवाओं की दशा में, फीस जुटाई गई निधि के प्रतिशत पर आधारित हो सकेगी ;

(च) ऋण वसूली सेवाओं की दशा में, फीस वसूले गए ऋणों के प्रतिशत पर आधारित हो सकेगी ;

(छ) लागत अनुकूलन से संबद्ध सेवाओं की दशा में, फीस उद्भूत फायदों के प्रतिशत पर आधारित हो सकेगी ; और

(ज) ऐसी कोई अन्य सेवा या संपरीक्षा, जो परिषद् द्वारा विनिश्चित की जाए ।”

36. उक्त विनियमों के विनियम 203 में,-

(i) मद सं. (14) में,-

(क) “कर्मचारिवृंद” शब्द के स्थान पर “अधिकारी और कर्मचारी” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “अध्यक्ष” शब्द के स्थान पर “कार्यकारी समिति” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) मद सं. (20) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(20क) अध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन रहते हुए संस्थान की ओर से सभी करारों, संविदाओं, विलेखों, दस्तावेजों और वचनबंधों आदि पर हस्ताक्षर करना ;”;

(iii) मद सं. (21) में, “वकालतनामों पर हस्ताक्षर करना” शब्दों के स्थान पर “संस्थान की ओर से न्यायालयों या मंचों या न्यायिक या अर्द्धन्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष सिविल या दांडिक या अन्य कार्यवाहियों के मामले में आवश्यक उपाय करना और वकालतनामों पर हस्ताक्षर करना” शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) मद सं. (23) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(23क) मद सं. (7), (9), (10), (11), (12), (16), (17), (18) और (19) के अधीन किन्हीं शक्तियों के प्रयोग या कर्तव्यों के निर्वहन के लिए संस्थान के किसी अधिकारी को प्राधिकृत करना, जैसा कि समय-समय पर आवश्यक समझा जाए ।”

37. उक्त विनियमों के विनियम 204 में, “अनुसूची ‘ग’, ‘घ’, ‘ङ’, ‘च’, ‘छ’ और ‘ज’ में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार उसके संबंध में” शब्दों और अक्षरों के स्थान पर “प्रबंध लेखा, निगम प्रबंध, कर प्रबंध, सूचना प्रणाली संपरीक्षा, बीमा और जोखिम प्रबंध तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन विषयों में अर्हतापश्च पाठ्यक्रमों के संबंध में” शब्द रखे जाएंगे ।

38. उक्त विनियमों की अनुसूची ‘क’ में,-

(i) सदस्यता प्रमाणपत्र से संबंधित प्ररूप “4” के प्रारंभिक पैरा में, “यह प्रमाणित किया जाता है कि के को तारीख20..... को संस्थान के एसोसिएट के रूप में प्रविष्ट किया गया था” शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“यह प्रमाणित किया जाता है कि के को तारीख20..... को संस्थान के एसोसिएट के रूप में प्रविष्ट किया गया था और वह अपने नाम के पश्चात् एसीए अक्षरों का उपयोग करने के लिए हकदार है ।”;

(ii) सदस्यता प्रमाणपत्र से संबंधित प्ररूप “5” के प्रारंभिक पैरा में, “यह प्रमाणित किया जाता है कि के को तारीख20..... को संस्थान के फेलो के रूप में प्रविष्ट किया गया था” शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“यह प्रमाणित किया जाता है कि के को तारीख20..... को संस्थान के फेलो के रूप में प्रविष्ट किया गया था और वह अपने नाम के पश्चात् एफसीए अक्षरों का उपयोग करने के लिए हकदार है ।”;

टी. कार्तिकेयन, सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधारण/104/12]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/134/88 तारीख 1 जून, 1988 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधन किया गया था :-

- अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/1/89 भारत के राजपत्र तारीख 7 अक्टूबर, 1989 में प्रकाशित;
- अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/10/90 भारत के राजपत्र तारीख 19 जनवरी, 1991 में प्रकाशित;
- अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/11/90 भारत के राजपत्र तारीख 19 जनवरी, 1991 में प्रकाशित;

- iv. अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/12/91 भारत के राजपत्र तारीख 23 फरवरी, 1991 में प्रकाशित;
- v. अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/13/90 भारत के राजपत्र तारीख 2 फरवरी, 1991 में प्रकाशित ;
- vi. अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/19/92 भारत के राजपत्र तारीख 7 मार्च, 1992 में प्रकाशित;
- vii. अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/28/95 भारत के राजपत्र तारीख 1 सितम्बर, 1995 में प्रकाशित;
- viii. अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/30/95 भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 13 मार्च, 1996 में प्रकाशित;
- ix. अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/31/97 भारत के राजपत्र तारीख 16 अगस्त, 1997 में प्रकाशित;
- x. अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/44/99 भारत के राजपत्र तारीख 26 फरवरी, 2000 में प्रकाशित;
- xi. अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/45/99 भारत के राजपत्र तारीख 26 फरवरी, 2000 में प्रकाशित;
- xii. अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/51/99 भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 17 अगस्त, 2001 में प्रकाशित;
- xiii. अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/59/2001 भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 28 सितम्बर, 2001 में प्रकाशित;
- xiv. अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/64 /2002 भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 31 मार्च, 2003 में प्रकाशित;
- xv. अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/64क/2003 भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 4 दिसम्बर, 2003 में प्रकाशित;
- xvi. अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/83/2005 भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 28 जुलाई, 2005 में प्रकाशित;
- xvii. अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/84/2005 भारत के राजपत्र, तारीख 17 जून, 2006 में प्रकाशित;
- xviii. अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/92 /2006 भारत के राजपत्र, तारीख 13 सितम्बर, 2006 में प्रकाशित;
- xix. अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/102/2007(ई) भारत के राजपत्र, तारीख 17 अगस्त, 2007 में प्रकाशित;
- xx. अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/116/2008 भारत के राजपत्र, तारीख 25 सितम्बर, 2008 में प्रकाशित;
- xxi. अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/123/2008 भारत के राजपत्र, तारीख 3 दिसम्बर, 2008 में प्रकाशित;

2255 GI/12-4

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2012

F. No. 1-CA(7)/145/2012.—Whereas certain draft regulations further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, were published as required by sub-section (3) of section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), in the notification of the Institute of Chartered Accountants of India No. 1-CA(7)/145/2012, dated the 23rd February, 2012, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 23rd February, 2012, inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 28th February, 2012;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft regulations have been considered by the Council of the Institute;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the said Act, the Council, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2012.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Chartered Accountants Regulations, 1988, (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1),—
 - (i) after clause (xiii), the following clause shall be inserted, namely:—

“(xiii a) “rules” means the rules made by the Central Government under the Act;”;
 - (ii) in clause (xv), for the words “or any Deputy”, the words “or any Additional or Joint or Deputy” shall be substituted.
3. In regulation 25C of the said regulations, for the words “Common Proficiency Test” wherever they occur, the words “Common Proficiency Course” shall respectively be substituted.
4. In regulation 25D of the said regulations,—
 - (i) in sub-regulation (1),—

(a) after the words, "Central Government", the words "or the State Government" shall be inserted;

(b) after the words "as equivalent thereto", the words "for the purposes of admission to graduation courses" shall be inserted.

(ii) after sub-regulation (1), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

"(1A) Any graduate or post graduate referred to in sub-clause (ix) of regulation 2 shall be exempted from passing the Common Proficiency Test under this regulation if such person is a -

(i) graduate or post graduate in commerce having secured in aggregate a minimum of fifty-five per cent. of the total marks or its equivalent grade in the examination conducted by any recognised University (including Open University) by studying any three papers of 100 marks each out of Accounting, Auditing, Mercantile Laws, Corporate Laws, Economics, Management (including Financial Management), Taxation (including Direct Tax Laws and Indirect Tax Laws), Costing, Business Administration or Management Accounting; or

(ii) graduate or post graduate other than those referred to in clause (i), having secured in aggregate a minimum of sixty per cent. of the total marks or its equivalent grade in the examination conducted by any recognised University (including Open University).

(1B) Any candidate who has passed the Intermediate examination conducted by the Institute of Cost Accountants of India set up under the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) or by the Institute of Company Secretaries of India set up under the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980) shall also be exempted from passing the Common Proficiency Test under this regulation.

Explanation.- For the purposes of sub-regulations (1A) and (1B),-

(i) for calculating the percentage of marks, the marks secured in subjects in which a person is required by the University (including open University) to obtain only pass marks and for which no special credit is given for higher marks, shall be ignored; and

(ii) any fraction of half or more shall be rounded up to the next whole number."

5. In regulation 28C of the said regulations,-

(a) for the words "Professional Competence Examination" wherever they occur, the words and brackets "Intermediate (Professional Competence) Examination" shall respectively be substituted;

(b) in sub-regulation (1),-

(i) in clause (a),-

(a) after the words, "Central Government", the words "or the State Government" shall be inserted;

- (b) after the words "as equivalent thereto", the words "for the purposes of admission to graduation courses" shall be inserted;
- (ii) (a) in clause (b), for the word "worked", the word "served" shall be substituted;
- (b) after the words "examination is held", the words "and has been so continuing on the first day of the said month" shall be inserted;
- (iii) in the second proviso, after the words, brackets and letters "to appear in the Professional Education (Examination-II)", the words, brackets and letter "and he fulfils the condition laid down under clause (b)" shall be inserted.

6. In regulation 28D of the said regulations, -

- (a) for the words "Integrated Professional Competence Course" wherever they occur, the words and brackets "Intermediate (Integrated Professional Competence) Course" shall respectively be substituted;
- (b) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(2) No candidate shall be eligible for enrolment to any of the level of the Intermediate (Integrated Professional Competence) Course, unless he -

- (a) has passed the Common Proficiency Test held under these regulations and Senior Secondary Examination (10+2 examination) conducted by an examining body constituted by law in India or an examination recognised by the Central Government or the State Government as equivalent thereto for the purposes of admission to graduation courses; or
- (b) has been exempted from passing Common Proficiency Test under regulation 25D.";

- (c) after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(2A) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2), a candidate who is pursuing the final year of graduation course shall be provisionally registered to the Intermediate (Integrated Professional Competence) Course which shall be confirmed only on submission of satisfactory proof of having passed the graduation examination with the minimum marks as provided in sub-regulation (1A) of regulation 25D within such period not exceeding six months as may be decided by the Council, from the date of appearance in the final year graduation examination:

Provided that if such candidate fails to produce the proof within the aforesaid period, his provisional registration shall be cancelled and the registration fee or the tuition fee, as the case may be, paid by him shall not be refunded and for the purpose of these regulations no credit shall be given for the theoretical education undergone."

7. In regulation 28E of the said regulations, -

(a) for the words "Integrated Professional Competence Examination", "Integrated Professional Competence Course" and "Professional Competence Examination" wherever they occur, the words and brackets "Intermediate (Integrated Professional Competence) Examination", "Intermediate (Integrated Professional Competence) Course" and "Intermediate (Professional Competence) Examination" shall respectively be substituted;

(b) in sub-regulation (1), after clause (b), the following proviso shall be inserted, namely,-

"Provided that a candidate who has been exempted from passing Common Proficiency Test under sub-regulation (1A) of regulation 25D and enrolled for the Intermediate (Integrated Professional Competence) Course shall be eligible to appear in the examination on completion of nine months of practical training under regulation 50.";

8. In regulation 29B of the said regulations, after the words "Professional Competence Examination" wherever they occur, the words and brackets "or the Intermediate (Professional Competence) Examination" shall respectively be inserted.

9. In regulation 29C of the said regulations, -

(A) in sub-regulation (1),-

(i) in clause (i),-

(a) for the words "Professional Competence Examination", the words and brackets "Intermediate (Professional Competence) Examination" shall be substituted;

(b) the word "and" occurring at the end, shall be omitted;

(ii) in clause (ii), after the words "examination is held", the words "or has been serving the last six months of practical training under regulation 50 on the first day of the month in which the examination is held" shall be inserted;

(iii) after clause (ii), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(iii) he produces a certificate to the effect that he has undergone a study course for such period, as on the first day of the month in which examination is held, in such manner as may be decided by the Council from time to time; and

(iv) completed the Advanced Course on Information Technology Training under these regulations for such period and in such manner as may be decided by the Council, from time to time.";

(iv) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that a candidate who has passed Professional Education (Examination-II) under the syllabus as decided by the Council under sub-regulation (5) of regulation 28B and has completed the practical training as is required for admission as a member on or before the last day of the

month preceding the month in which the examination is held or has been serving the last twelve months of practical training including excess leave, if any, on the first day of the month in which the examination is held and has completed the said study course and Advanced Course on Information Technology Training, shall be admitted to the Final Examination.”;

(B) in sub-regulation (2),-

- (a) after the words “Integrated Professional Competence Examination”, the words and brackets “or Intermediate (Integrated Professional Competence) Examination” shall be inserted;
- (b) after the words “examination is held” occurring at the end, the words “and has completed the aforesaid study course and Advanced Course on Information Technology Training” shall be inserted.

10. In regulation 31 of the said regulations, -

- (i) in clause (ii), for the words “Professional Competence Examination”, the words and brackets “Intermediate (Professional Competence) Examination” shall be substituted;
- (ii) in clause (iii), for the words “Integrated Professional Competence Course”, the words and brackets “Intermediate (Integrated Professional Competence) Course” shall be substituted.

11. For regulation 36A of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

“36A Requirement for passing Common Proficiency Test.— A candidate for the Common Proficiency Test shall ordinarily be declared to have passed the test if he obtains at one sitting a minimum of thirty per cent. marks in each section and a minimum of fifty per cent. marks in the aggregate of all the sections, subject to the principle of negative marking, in such manner as may be determined by the Council, from time to time.

Explanation.- For the removal of doubt, it is hereby declared that the provisions of this regulation shall apply to a Common Proficiency Test held on or after the commencement of the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2012.”.

12. In regulation 37B of the said regulations, for the words “Professional Competence Examination” wherever they occur, the words and brackets “Intermediate (Professional Competence) Examination” shall respectively be substituted.

13. In regulation 37C of the said regulations, -

- (i) for the words “Integrated Professional Competence Examination” wherever they occur, the words and brackets “Intermediate (Integrated Professional Competence) Examination” shall respectively be substituted;
- (ii) for the words “Professional Competence Examination” wherever they occur, the words and brackets “Intermediate (Professional Competence) Examination” shall respectively be substituted;
- (iii) in sub-regulation (2), clause (a) shall be omitted.

14. In regulation 40 of the said regulations, -
- (i) for the words "Professional Competence Examination", the words and brackets "Intermediate (Professional Competence) Examination" shall be substituted;
 - (ii) for the words "Integrated Professional Competence Examination", the words and brackets "Intermediate (Integrated Professional Competence) Examination" shall be substituted.
15. In regulation 43 of the said regulations, -
- (i) after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-
 "(2A) A member in full time employment with a firm of chartered accountants shall be entitled to train one articled assistant provided he has been in employment with the same firm for a continuous period of three years.";
 - (ii) in sub-regulation (3), clause (i) shall be omitted.
16. In regulation 45 of the said regulations,-
- (i) for the words "Integrated Professional Competence Course" wherever they occur, the words and brackets "Intermediate (Integrated Professional Competence) Course" shall be substituted;
 - (ii) in sub-regulation (1), in clause (b), -
 - (a) for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:-
 "(i) has passed the Professional Education (Examination-II) or has passed Group I level or Accounting Technician level of Intermediate (Integrated Professional Competence) Examination held under these regulations or has been exempted from passing Common Proficiency Test under sub-regulation (1A) of regulation 25D; and";
 - (b) in sub-clause (ii), after the words "so specified", the word "and" shall be inserted;
 - (c) after sub-clause (ii), the following sub-clause shall be inserted, namely:-
 "(iii) has completed the Orientation Course for such period and in such manner and within such time as may be decided by the Council from time to time.";
 - (iii) in sub-regulation (2),
 - (a) after the words "Central Government", the words "or the State Government" shall be inserted;
 - (b) after the words "as equivalent thereto", the words "for the purposes of admission to graduation courses" shall be inserted.

17. In regulation 50 of the said regulations, --

- (i) in the third proviso, for the words "Professional Competence Examination", the words and brackets "Intermediate (Professional Competence) Examination" shall be substituted;
- (ii) for fourth Proviso, the following provisos shall be substituted, namely:-

"Provided also that a candidate enrolled for the Intermediate (Integrated Professional Competence) Course shall be eligible to three years of articles training on his passing the Group I level or Accounting Technician level of the Intermediate (Integrated Professional Competence) Examination:

Provided also that a candidate who is a graduate or post graduate and has been exempted from passing the Common Proficiency Test shall be eligible to three years of articles training on his registration to the Intermediate (Integrated Professional Competence) Course."

18. In regulation 51 of the said regulations, in sub-regulation (1), for the words "Professional Competence Examination", the words and brackets "Intermediate (Professional Competence) Examination" shall be substituted.

19. After regulation 51B of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely:-

"51C. Advanced Course on Information Technology Training. - A candidate shall undergo an Advanced Course on Information Technology Training as may be determined by the Council which shall not be less than one hundred hours and not more than five hundred hours and in such manner and within such time as may be determined by the Council from time to time."

20. In regulation 69 of the said regulations,-

- (a) in sub-regulation (1), in clause (b), for sub-clauses (ii) and (iii), the following sub-clauses shall respectively be substituted, namely:-

"(ii) has passed the Professional Education (Examination-II) or Group I level or Accounting Technician level of Intermediate (Integrated Professional Competence) Examination held under these regulations or has been exempted from passing the Common Proficiency Test under sub-regulation (1A) of regulation 25D; and

(iii) has successfully completed computer training programme or Information Technology Training, for such period, in such manner and within such time as may be decided by the Council from time to time; and"

- (b) after sub-clause (iii), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(iv) has completed the Orientation Course for such period, in such manner and within such time as may be decided by the Council from time to time."

21. In regulation 72 of the said regulations, in sub-regulation (1), for the words "Professional Competence Examination", the words and brackets "Intermediate (Professional Competence) Examination" shall be substituted.

22. After regulation 72B of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely:-

"72C. Advanced Course on Information Technology Training. - A candidate shall undergo the Advanced Course on Information Technology Training as may be determined by the Council which shall not be less than one hundred hours and not more than five hundred hours and in such manner and within such time as may be determined by the Council from time to time."

23. In regulation 127 of the said regulations, in sub-regulation (1), for item 4, the following item shall be substituted, namely:-

"4. The States of Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttarakhand and Uttar Pradesh."

24. In regulation 130 of the said regulations, in sub-regulation (2), -

(i) in clause (xvii), the word "and" occurring at the end shall be omitted;

(ii) after clause (xvii), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(xvii a) to publish Newsletter for dissemination of useful information;

(xvii b) to conduct Continuing Professional Education Programmes on topics of professional relevance; and".

25. In regulation 134 of the said regulations,-

(i) in sub-regulation (1), -

(a) for the words "April of the year", the words "April of the financial year" shall be substituted;

(b) after the proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided further that, if the professional address is not borne on the Register on the relevant date, the residential address borne on the Register shall determine his regional constituency:

Provided also that, in the case of a member having his professional address outside India and eligible to vote, his regional constituency shall be determined according to his professional address in India registered immediately before he went abroad or the residential address in India borne on the Register on the relevant date, whichever is later."

(ii) in sub-regulation (2),--

(a) for the words "April of the year", the words "April of the financial year" shall be substituted;

(b) for the words "on the date of election", the words "on the last date of scrutiny of nominations" shall be substituted;

(c) the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that no person shall be eligible to stand for election to a Regional Council, if—

- (a) he is holding a post under the Central Government or State Government;
- (b) he is or has been elected as a member to Regional Council for more than three consecutive terms; or
- (c) he is or has been elected as the Chairman under regulation 137:

Provided further that, no person who has been found guilty of any professional or other misconduct and whose name is removed from the Register or has been awarded penalty of fine, shall be eligible to stand for election to a Regional Council,—

- (i) in case of misconduct falling under the First Schedule to the Act, for a period of three years;
- (ii) in case of misconduct falling under the Second Schedule to the Act, for a period of six years,

from the completion of the period of removal of name from the Register or payment of fine, as the case may be:

Provided also that, no person who has been auditor of the Regional Council shall be eligible to stand for election to a Regional Council for a period of three years after he ceases to be the auditor of that Regional Council.”;

(iii) in sub-regulation (3), for the words and figures “under regulation 85”, the words, figures and brackets “under rule 8 read with Schedule 3 to the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006” shall be substituted;

(iv) for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(4) (i) At least three months before the date of election, the Council shall publish, for each regional constituency, a list of members eligible to vote showing distinctly and separately -

- (a) whether the voter is an associate or a fellow;
- (b) the address of each member as determined under sub-regulation (1) for deciding the eligibility of the member to vote;
- (c) in the case of a voter residing outside India, in addition to his address in India under sub-clause (b), his address outside India if furnished to the Institute by the voter concerned;

- (d) details of internet address or e-mail address as furnished by a voter to the Institute, provided an express consent is given by the voter for its inclusion in the list of voters;
 - (e) the manner in which the voter shall exercise his franchise; and
 - (f) in case the voter is to exercise his franchise at a polling booth, the number and address of the polling booth, at which the franchise shall be exercised.
- (ii) Subject to the provisions of these regulations, the address of a member published in the list of voters for determining the manner in which he shall be entitled to cast his vote, the constituency and the polling booth to which he shall belong for the purpose of casting his vote, shall be final.
 - (iii) The inclusion of the name of a member in the list of members eligible to vote shall not confer an absolute right to vote at the election which shall be subject to the other provisions of these regulations, the Act and the rules made thereunder.
 - (iv) The list of members eligible to vote shall be made available at the Headquarters of the Regional Council and its branches on payment of such price as may be fixed by the Council.
 - (v) An announcement about the availability of the list, shall be put on the website of the Regional Council, the notice board of the Regional Council, as well as the notice board of the branches of the Regional Council, wherever these exist.
 - (vi) If a clerical mistake or omission is detected in the list of members eligible to vote, the Secretary may rectify such mistake at any time by issue of a suitable corrigendum.”;
- (v) in sub-regulation (6), -
 - (i) in clause (i), for the words “appropriate form”, the words “form approved by the Council” shall be substituted;
 - (ii) for clause (ii), the following clauses shall be substituted, namely:-
 - “(ii) delivered along with requisite fees, security deposit and other papers required for the purpose in the form approved by the Council to the Secretary by name not later than 6 P.M. on the notified date:

Provided that no nomination delivered after the last date and time notified for the election shall be entertained by the Panel for scrutiny of nominations.

 - (iii) An acknowledgement of delivery shall be issued by the Secretary or by a person authorised by him on receipt of nomination form mentioning the time and date of receipt of nomination form.”;

- (vi) after sub-regulation (6), the following sub-regulation and Explanation shall be inserted, namely:-

“(6A) The nomination shall be valid only if it is accompanied by a statement signed and verified by the candidate containing the information called for.

Explanation.— For the purpose of this sub-regulation, a valid nomination means a nomination which contains all the particulars called for through the nomination form and incomplete nomination without one or more particulars shall liable to be rejected.”;

- (vii) in sub-regulation (7), for the words “one thousand rupees”, the words “twenty-five thousand rupees” shall be substituted;

- (viii) after sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(7A) A candidate for election, in addition to fee as provided in this Chapter shall pay, irrespective of the number of nominations filed, an amount of ten thousand rupees as security deposit, which shall be forfeited if he fails to secure not less than one per cent. of the original votes polled in the concerned regional constituency.”;

- (ix) in sub-regulation (8), for the words “in consultation with and approval”, the words “with the prior approval” shall be substituted;

- (x) after sub-regulation (9), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(9A) At the time of giving his decision, the President may -

- (a) dismiss the dispute referred to him under sub-regulation (9);
- (b) declare the election of all or any of the elected candidates to be void;
- (c) declare the election of all or any of the elected candidates to be void and declare the applicant or any other candidate to have been duly elected; or
- (d) may pass such order as to costs as he may consider appropriate.”;

- (xi) in sub-regulation (10), for the words and figures “prescribed in Chapter VI of these regulations”, the words, brackets and figures “specified in the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006” shall be substituted.

26. In regulation 135 of the said regulations, in sub-regulation (4), the Explanation shall be omitted.

27. In regulation 137 of the said regulations,-

- (i) in clause (i) of sub-regulation (1), for the word “September”, the word “February” shall be substituted;

- (ii) in sub-regulation (7), in clause (i), after item (e), the following item shall be inserted, namely:-

"(f) Continuing Professional Education Committee.";

- (iii) in sub-regulation (11), for the word "September", the word "February" shall be substituted.

28. In regulation 141 of the said regulations, in the proviso to sub-regulation (1), for the word "September", the word "February" shall be substituted.

29. In regulation 149 of the said regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(1) The Regional Council shall, on a requisition made in writing by at least ten per cent. of the total number of members of the region or seven hundred fifty members in the region, whichever is less, convene an extraordinary General Meeting."

30. In regulation 159 of the said regulations,-

- (i) in sub-regulation (1), for the figures and word "100 members", the figures and word "150 members" shall be substituted;

- (ii) after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(1A) The Council may also, by notification in the Gazette of India, set up a branch of a Regional Council at such place in a district in which neither the Headquarters of the Regional Council nor a branch of the Regional Council is located, provided there are minimum 100 members having their addresses registered in that district."

31. After regulation 161 of the said regulation, the following regulation shall be inserted, namely:-

"161A. Meetings of Council through teleconferences or video conferences. - A meeting of the Council, through teleconferencing or video conferencing may, at any time, be called subject to such conditions as may be determined by the Council from time to time."

32. After regulation 169 of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely:-

"169A. Meetings of Standing Committee through teleconferences or video conferences. - A meeting of the Standing Committee, through teleconferencing or video conferencing may, at any time, be called subject to such conditions as may be determined by such Committee from time to time."

33. In regulation 177 of the said regulations, in sub-regulation (3), after the words and figures "in regulations 169", the figures and letter "169A", shall be inserted.

34. In regulation 184, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(1) Where a holder of a certificate granted by the Council has lost it, the Council may, on an application made in this behalf, duly supported by an affidavit of the applicant to the effect that he was in possession of such a certificate and had lost it, issue a duplicate, -

- (a) in case of a certificate of membership or a certificate of practice as an associate or fellow on payment of a fee of five hundred rupees; and
- (b) in case of any other certificate issued under these regulations, on payment of a fee of two hundred rupees."

35. In regulation 192 of the said regulations, in the proviso,-

(i) in clause (b), the word "and" occurring at the end shall be omitted;

(ii) after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:-

- "(d) in the case of certain management consultancy services as may be decided by the resolution of the Council from time to time, the fees may be based on percentage basis which may be contingent upon the findings, or results of such work;
- (e) in the case of certain fund raising services, the fees may be based on a percentage of the fund raised;
- (f) in the case of debt recovery services, the fees may be based on a percentage of the debt recovered;
- (g) in the case of services related to cost optimisation, the fees may be based on a percentage of the benefit derived; and
- (h) any other service or audit as may be decided by the Council."

36. In regulation 203 of the said regulations,-

(i) in item (14),-

- (a) for the word "staff", the words "officers and employees" shall be substituted;
- (b) for the word "President", the words "Executive Committee shall" shall be substituted;

(ii) after item (20), the following item shall be inserted, namely:-

"(20A) signing all agreements, contracts, deeds, documents and undertaking, etc., on behalf of the Institute subject to the approval of the President;";

(iii) in item (21), for the words "signing vakalatnamas", the words "taking necessary steps in matters of any civil or criminal or other proceeding on behalf of the Institute in courts or forums or judicial or quasi-judicial authorities and signing vakalatnamas" shall be substituted;

(iv) after item (23), the following item shall be inserted, namely:-

"(23A) authorising any officer of the Institute to exercise or discharge any powers or duties under items (7), (9), (10), (11), (12), (16), (17), (18) and (19), as may be considered necessary from time to time."

37. In regulation 204 of the said regulations, for the words and letters "in connection therewith in accordance with the rules contained in Schedules 'C', 'D', 'E', 'F', 'G' and 'H' ", the words "in connection with the post qualification courses in Management Accountancy, Corporate Management, Tax Management, Information Systems Audit, Insurance and Risk Management, and International Trade Laws and World Trade Organisation" shall be substituted.

38 In Schedule A to the said regulations, -

(i) in Form "4" relating to Certificate of Membership in the opening paragraph, for the words and figures "This is to certify that of was admitted as an Associate of the Institute on the day of..... 20.....", the following shall be substituted, namely:-

"This is to certify that of was admitted as an Associate of the Institute on the day of..... 20... and he/she is entitled to use the letters A.C.A. after his/her name.";

(ii) in Form "5" relating to Certificate of Membership in the opening paragraph, for the words and figures "This is to certify that of was admitted as a Fellow of the Institute on the day of..... 20.....", the following shall be substituted, namely:-

"This is to certify that of was admitted as a Fellow of the Institute on the day of..... 20... and he/she is entitled to use the letters F.C.A. after his/her name."

T. KARTHIKEYAN, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./104/12]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number 1-CA(7)/134/88, dated the 1st June, 1988 and subsequently amended by the following notification numbers:-

- (i) Notification No.1-CA(7)/1/89 published in the Gazette of India, dated the 7th October, 1989;
- (ii) Notification No.1-CA(7)/10/90 published in the Gazette of India, dated the 19th January, 1991;
- (iii) Notification No.1-CA(7)/11/90 published in the Gazette of India, dated the 19th January, 1991;
- (iv) Notification No.1-CA(7)/12/91 published in the Gazette of India, dated the 23rd February, 1991;
- (v) Notification No.1-CA(7)/13/90 published in the Gazette of India, dated the 2nd February, 1991;
- (vi) Notification No.1-CA(7)/19/92 published in the Gazette of India, dated the 7th March, 1992;
- (vii) Notification No.1-CA(7)/28/95 published in the Gazette of India, dated the 1st September, 1995;
- (viii) Notification No.1-CA(7)/30/95 published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 13th March, 1996;
- (ix) Notification No. 1-CA(7)/31/97 published in the Gazette of India, dated the 16th August, 1997;

- (x) Notification No. 1-CA(7)/44/99 published in the Gazette of India, dated the 26th February, 2000;
 - (xi) Notification No.1-CA(7)/45/99 published in the Gazette of India, dated the 26th February, 2000;
 - (xii) Notification No.1-CA(7)/51/2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 17th August, 2001;
 - (xiii) Notification No.1-CA(7)/59/2001 published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 28th September, 2001;
 - (xiv) Notification No.1-CA(7)/64/2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 31st March, 2003;
 - (xv) Notification No.1-CA(7)/64A/2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 4th December, 2003;
 - (xvi) Notification No.1-CA(7)/83/2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 28th July, 2005;
 - (xvii) Notification No.1-CA(7)/84/2005 published in the Gazette of India, dated the 17th June, 2006;
 - (xviii) Notification No. 1-CA(7)/92/2006 published in the Gazette of India, dated the 13th September, 2006;
 - (xix) Notification No. 1-CA(7)/102/2007(E) published in the Gazette of India, dated the 17th August, 2007;
 - (xx) Notification No.1-CA(7)/116/2008 published in the Gazette of India, dated the 25th September, 2008;
 - (xxi) Notification No.1-CA(7)/123/2008 published in the Gazette of India, dated the 3rd December, 2008.
-